shall come into force from April 1, 1992.

(5) Regular enforcement drive is being carried out on the roads of capital against the vehicles which are not conforming to the prescribed standards.

(6) Directorate of Transport, Delhi Administration has launched an a wareness campaign about vehicular pollution, health hazards as well as maintenance of procedures to control vehicular pollution.

(7) Checking facilities have been provided to assess pollution from vehicles as well as facilities for rectification by tuning of the engine.

(8) The Government has started a programme of running battery powered buses so as to minimise vehicular pollution and improve the ambient air ouality in congested areas of traffic.

(c) The use of Methanol and Ethanol as a substitute for diesel has been extensively evaluated both in the laboratory as well as in the field through three large demonstration projects by the Indian Institute of Petroleum, Dehradun. These have shown that the use of alcohol can replace about 15—20 per cent diesel fuel in the dual fuel mode operation for all diesel engines. This can also reduce considerably the visible smoke as also carcinogenic emissions.

वनों की कटाई को रोका जाना

958. **डा० अबरार अहमद** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण की दृष्टि से वनों के कटाव को रोकने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1980 में सम्पूर्ण देश में और राजस्थान में कितना वनाच्छादित भूभाग था और 1990 में यह क्षेत्र घटकर कितना रह गया ;

(ग) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश और राजस्थान में वनों के संरक्षण पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ; और

(घ) इस संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) हमारी राष्ट्रीय वन नीति का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना तथा पारिस्थतिकीय सन्तुलन बनाये रखना है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

1. वन भूमि के वनेतर प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल को रोकने के लिए 1980 में पारित वन (संरक्षण) अधिनियम को अधिक कड़ा बनाने के लिए 1988 में उसमें संशोधन किया गया।

2. "वनों का जैविक हस्तक्षेप संरक्षण करने के लिए अवसंरचना का विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में लागू की जा रही है ।

3. राज्यों/संघ शासित राज्यों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं :—

   1. प्राकृतिक वनों की कटाई को रोकना और जहां इस प्रकार की कटाई फसल अथवा अन्य वनवर्धन प्रयोजनों के लिए अपरिहार्य हो, वहां इसे पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम 10 हेक्टेयर तक तथा मैदानी इलाकों में 25 हेक्टेयर तक सीमित रखा जाना चाहिए।

   2. पहाड़ियों में 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कम से कम कुछ वर्षों के लिए वृक्षों की कटाई पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करना।

   3. पहाड़ियों और पर्वतों में ऐसे नाजुक क्षेत्रों का पता लगाना, जहां वनों की कटाई से संरक्षण और बड़े पैमाने पर तत्काल वनरोपण की आवश्यकता है ।

4. कुल भौगोलिक क्षेत्र के 4 प्रतिशत को वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और जीवमंडल रिज़र्वों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के रूप में रखना।

(ख) 1981–83 की अवधि से सम्बन्धित स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1987 के अनुसार, देश में और राजस्थान में वास्तविक वन आच्छादन क्रमश: 64.2 मिलियन हे० और 1.24 मिलियन हेक्टेयर था। किन्तु 1987–89 की अवधि के सम्बन्ध में, उपग्रह प्रतिबिम्बिकी के दृश्य विवेचन के आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किये गए वन आच्छादन के नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार, देश में वास्तविक वन आच्छादन 64.06 मिलियन हेक्टेयर और राजस्थान में 1.29 मिलियन हेक्टेयर है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

Narmada Sagar Dam, Madhya Pradesh

959. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large forest area has been affected in the Narmada Sagar dam area in Madhya Pradesh;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether any afforestation plan has been initiated in the area by the Central and State Governments; and

(d) if so, what progress Government have so far made in the afforestation of the area in Madhya Pradesh?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) Narmada Sagar Project involves diversion of 41,111.97 ha. forest area for which approval has been accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 on 7-10-87.

(c) and (d) As per stipulated condition, compensatory afforestation is required to be done over 10,141.848 ha. non-forest area and 70,80,1.587 ha. degraded forest area. So far, compensatory affrestation has been done over 5,239 ha. of non-forest land and 23,048 ha. degraded forest land.

960. [Transferred to the 12th March, 1992]

Action plan to clean Narmada and Betwa Rivers

961. SHRI SURENDRA SINGH THAKUR: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have chalked out any 'Action Plan' for cleaning the water of inter-state rivers;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government have prepared any action plan for cleaning of Narmada and Betwa rivers in Madhya Pradesh with a view to remove pollutants from these rivers and make their water hygienic and worth drinking;

(d) if reply to (c) be in affirmative, what steps have been taken by the Central Government so far to carry out the action plan; and

(e) if reply to (c) be in negative, what steps Government propose to take to provide healthy and hygienic water from these rivers for drinking purpose?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) A National River Action Plan for abatement of pollution in the grossly polluted stretches of major inter-state rivers is under formulation. Details in this regard are being worked out.

(c) to (e) Pollution surveys in some stretches of the rivers Narmada and Betwa in Madhya Pradesh are in progress. Depending upon the results of these surveys and *inter-se* priority fixed therefrom, these stretches would be considered in formulating the proposed NRAP.